

प्रसार भारती
आकाशवाणी शिमला
04.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ओ.पी.एस. लागू करने के कारण प्रदेश के खजाने पर विपरीत असर पड़ा है। इसके बावजूद सरकार ने एक लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस लागू किया है और यह फैसला राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर लिया गया है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर साल अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा एक हजार 6 सौ करोड़ रुपये कम कर दी है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से राज्य में 26 हजार 3 सौ 24 कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से 5 हजार 3 सौ 56 को ओपीएस दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 7 हजार 53, 2023-24 में 7 हजार 2 सौ 17 और वर्ष 2024-25 में 6 हजार 6 सौ 98 कर्मचारी ओपीएस में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों का एनपीएस का लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार के पास जमा है।

प्वाइंट ऑफ ऑर्डर

छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बीते रोज हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विपक्षी दल भाजपा ने आज विधानसभा से वाकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाया और कहा कि एसडीएम धर्मशाला ने विद्यार्थी परिषद को टैक्सी स्टैंड से जोरावर स्टेडियम तक विरोध मार्च की अनुमति दी थी। इसकी सूचना एसडीएम ने संबंधित एसएचओ को भी दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल सदन में कहा था कि विद्यार्थी परिषद को विरोध मार्च की अनुमति नहीं दी थी। जयराम ठाकुर ने शिमला में एस.डी.एम. शहरी द्वारा दृष्टिहीनों के साथ की गई बदसलूकी का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सदन से वाकआउट कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बीते रोज भी सदन में कहा था कि विद्यार्थी परिषद को केवल विरोध मार्च की इजाजत थी न कि धरने या रैली की।

प्वाइंट ऑफ ऑर्डर-2

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के वाकआउट की निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भाजपा ने यह वाकआउट राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया, जो निंदनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में भाजपा विधायक अपनी पार्टी की रैली में जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस की कथित झड़प की आड़ ली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को टैक्सी स्टैंड से जोरावर स्टेडियम तक विरोध मार्च की अनुमति दी गई थी, लेकिन विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक आने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बैरीगेट्स तोड़ दिए। इस पर उनकी पुलिस से झड़प हो गई और उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया।

आइस स्केटिंग

राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिक में आज से स्केटिंग के सत्र शुरू हो गए हैं। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया

कि आज सुबह स्केटिंग का पहला सत्र करवाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार एक सप्ताह पहले स्केटिंग शुरू हो गई है।

स्केटिंग करने पहुंचे बच्चे बेहद उत्साहित दिखे और उन्होंने बताया कि इन दिनों स्कूलों में छुट्टियां रहती हैं जिससे उन्हें स्केटिंग करने का अच्छा समय मिलेगा।
